by UK is concerned. This is a question which was discussed here. We will be able to get some few other markets under the general scheme of preference given by EEC.

SHRI SHIVAJI RAO S. DESHMUKH How long it take for this Government to be aware of the fact that even if cotton is given free to the textile mills yet the textiles are bound to be the costliest in the world because one kilo of lint yields 7 sq metres of cloth and the cost of cloth is 20 times the cost of one kilo of lint. How long is the Government going to persist with the cheap cotton policy.

SHRI L. N. MISHRA : The cotton policy is a different thing Here it is a question of total production of textiles Our mill production is costlier because we have old mills Mr. Deshmukh will agree with me that as against the support prices of Rs 1,300 or Rs. 1,400 per bale the ruling price is Rs. 3,600 per bale Naturally, it adds to our cost of production

Communication Facilities in Eastern U P.

*1694 SHRI K. C. PANDEY Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state

(a) whether inadequate communication facilities available in the Eastern Districts of Uttar Pradesh impede the development of the region ; and

(b) if so, the special steps which are being taken in this direction ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा): (क) जी नहीं, पूर्वी जिलों में उपलब्ध डाक और दूर-संचार सुविधाएं अपर्याप्त नहीं समझी जातीं। हमारे पास जो साधन थे उनसे इससे अधिक सफलता संभव नहीं थी।

(i) **दूर संचार :**

उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में 10 जिले हैं। इन जिलों के सभी सदर मुकामों, सब-डिवीजनल सदर मुकामों तहसीलों के सदर मुकामों और 20,000 से अधिक आबादी वाली जगहों में टेलीफोन और तार की सुविधाएं दे दी गई हैं। 50 फी सदी से अधिक ऐसे थानों में जिनके इंचार्ज सब-इंस्पेक्टर हैं और ब्लाकों के सदर मुकामों और 5,000 से अधिक आबादी वाले स्थानों में तार सुविधाएं दी जा चुकी हैं।

इस समय इन जिलों में 51 टेलीफोन एक्सचेंज, 86 सार्वजनिक टेलीफोन घर और 209 तारघर काम कर रहे हैं।

(ii) **डाक :—**

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जितनी डाक सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें अपर्याप्त नहीं माना जाता जैसा कि सभा-पटल पर रखे विवरण-I से स्पष्ट है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि इन जिलों में 4 टेलीफोन एक्सचेंज, 40 सार्वजनिक टेलीफोन घर और 68 तारघर खोलने का प्रस्ताव है।

चौथी पंच-वर्षीय योजना के बाकी तीन वर्षों में इन जिलों में नये खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है, जिसे सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण-I

जिलों के नाम	1-4-71 को काम कर रहे डाक घरों की संख्या	प्रत्येक डाक घर औसतन कितने क्षेत्र और आबादी को सेवा प्रदान करता है।		किसी व्यक्ति को डाकघर तक पहुँचने के लिए औसतन कितनी अरीय दूरी तै करनी पड़ती है (दूरी किलोमीटर में)
		क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर में)	आबादी	
1	2	3	4	5
आजमगढ़	440	16	4631	2.00

1	2	3	4	5
बलिया	252	12	4915	1.70
बस्ती	328	22	7576	2 40
देवरिया	337	15	7048	1 90
फैजाबाद	373	12	4475	1.70
गाजीपुर	226	18	4903	2 10
गोंडा	311	23	6420	2.40
गोरखपुर	442	13	4526	1.80
जौनपुर	284	13 80	5956	1.80
वाराणसी	291	22 50	8034	2.10
1-7-71 को पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति	13320	21 84	5536	2.30

विवरण-II

जिले का नाम	नीचे दिये गये वर्षों मे डाकघर खोले जाने के प्रस्ताव		
	1971-72	1972-73	1973-74
आजमगढ	14	12	10
बलिया	11	8	10
बस्ती	7	7	7
देवरिया	16	11	11
फैजाबाद	10	10	10
गाजीपुर	13	11	8
गोंडा	7	7	7
गोरखपुर	19	14	9
जौनपुर	10	10	10
वाराणसी	12	9	3
पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति	300	300	300

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : हमारे संचार मंत्री जी पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याओं से पूर्णरूप से अवगत हैं। हमारे यहां दोआबा जिसे सरयू और घाघरा का दोआबा बोला जाता है 14-14 और 22-22 मील से लोग तार देने के लिए खलीलाबाद आते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि नौगढ़ से गोरखपुर लाइन गई हैं जबकि बस्ती हमारा जिला पड़ता है तो क्या मंत्री महोदय नौगढ़ से सीधी लाइन बस्ती के लिए कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मान्यवर, अब यह सवाल बड़े डिटेल का है अर्थात् उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में संचार सुविधायें सुलभ करने से सम्बन्धित है तो उसके लिए माननीय सदस्य कोई विशेष सुझाव देंगे तो उस पर विचार किये बगैर हम चैन नही लेंगे।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : क्या संचार मंत्री जी को इस प्रकार का कोई ससद् सदस्यो से प्रतिवेदन मिला है कि उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में विशेष कर पर्वतीय क्षेत्रो में मैदानी इलाकों के मुकाबले, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष परिस्थितिया रहती हैं, इसलिए वहा पर संचार सुविधाये देने का नौर्म भिन्न होना चाहिए, यदि हां, तो उसके ऊपर उनका क्या विचार है ?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : जी हां, काश्मीर से लेकर नेफा तक के जितने उन पर्वतीय क्षेत्रों से सम्बन्धित पार्लियामेंट के मैम्बर्स हैं उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया है जिसमें यह मांग की है कि पहाड़ी इलाकों में जो हमारा नौर्म हो तार, टेलीफोन और डाकखाने आदि खोलने का वह मैदानी इलाकों मे यह सुविधाएं देने के नौर्म से भिन्न होना चाहिए। उनके उस प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : सहानुभूति के साथ विचार किया जा रहा है ?

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : जी हां, बिना सहानुभूति के हमारा कोई काम नहीं होता है।

Facilities to National Political Parties to propagate their View-points over T.V.

*1695. SHRI N E HORO : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to allow the National Political Parties to place their view-points before the public through the Television facilities ; and

(b) if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI NANDINI SATPATHY) : (a) and (b). There is at present no such proposal under consideration. However, Government have an open mind on the question of allocation of time on A.I.R and television to national political parties provided there is a common acceptance of ground rules and framework within which political debate in our country is conducted. In the meantime, the Hon'ble Member will appreciate that both A.I.R. and T.V. in their news commentary and other programmes do report and reflect the varying Political views in our country.

SHRI N. E. HORO : The Government in their reply say that they are keeping an open mind on the question of allocation of time on the AIR and television. I would like to know why Government is afraid of immediately allowing the national parties to utilise the media of AIR and television. The Government's reply seems to be 'No' in a roundabout way. I want the Government to allow time to the national parties on the AIR and television.

SHRIMATI NANDINI SATPATHY : Government is not at all afraid of allowing political parties to have their say on television and AIR ; on the other hand, before the last election and before that also, before the last to the last general election, there was a proposal for the political parties to have their say on the radio, but because they could not come to an agreement, it could not materialise.